

दिनांक 23/25 फरवरी, 1985

सं० शो० वि०/रोहतक/147-84/6944.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मौं प्रशासक नगरपालिका, रोहतक, के श्रमिक श्री दलीप सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रोवोगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चाहनीय समझते हैं ;

इसलिए, प्रब, ग्रोवोगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 की घारा 10 की उपघारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्रधिसूचना सं० 9641-१-श्रम/70/3257, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी प्रधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ.(ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त प्रधिनियम की घारा 7 के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री दलीप सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो. वि./सोनीपत/237-84/6951.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मौं एम. के. गलाग इण्डस्ट्रीज, प्रा. लि. जी. टी. रोड, सोनीपत के श्रमिक श्री महेंद्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रोवोगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चाहनीय समझते हैं ;

इसलिए, प्रब, ग्रोवोगिक विवाद प्रधिनियम, 1947, की घारा 10 की उप-घारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्रधिसूचना सं० 9641-१-श्रम/70/3257, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी प्रधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ.(ई)श्रम/70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त प्रधिनियम की घारा 7 के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री महेंद्र सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० शो० वि०/सोनीपत/236-84/6958.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि गोड़ पोलो फिब. एम/16 इण्डस्ट्रीजल एरिया-सोनीपत, के श्रमिक श्री सूबे सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रोवोगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चाहनीय समझते हैं ;

इसलिए, प्रब, ग्रोवोगिक विवाद प्रधिनियम, 1947, की घारा 10 की उपघारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्रधिसूचना सं० 9641-१-श्रम/70/3257, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी प्रधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ.(ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त प्रधिनियम की घारा 7 के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री सूबे सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो. वि./रोहतक/145-84/6965.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मौं प्रशासक नगरपालिका, रोहतक के श्रमिक श्री चन्द्रपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रोवोगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चाहनीय समझते हैं ;

इसलिए, भ्रव, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की घारा 10 की उपघारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई जक्षियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, घारा 11 प्रयुक्ति राम की घारा 7 के प्रयोग गठित श्रम व्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे संसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा पामता व्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से संसंगत या संबंधित मामला है:—

क्या श्री चन्द्रपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 28 फरवरी, 1985

सं. श्री. वि./रोहता/ ८-८५/७५०२.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मोहन स्वीकृति मिल, रोहतक, के अधिक श्री रमेश चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना धार्छनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित भरताभा अधिसूचना सं. 3864-ए-एरा. श्रो. (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री रमेश चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो.वि./रोहतक/ 5-85/ 7509.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मोहन स्पीनिंग मिल, रोहतक, के अधिक व्यापक जगदीश चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हृतियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निविष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, प्रबंध, भौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं 3864-ए-एस. श्रो. (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादशस्त्र या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायमिण्य हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों द्वाया अभिक के बीच या सो विवादशस्त्र मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अन्यवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री जगदीश चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हृकदार है ?

सं. ग्रो. वि./सोनीपत्त/246-84/7545.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की रोप है कि मैं गोल्डी हाई सेक्स पौलटरी काम निः०, वैगा गन्तव्य (सोनीपत्त). के अधिक श्री कर्मवीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद सिखित मामले में कोई आद्विग्निक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांधनीय समझते हैं;

इस लिए, प्रब, मीडोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-ए-अम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस.ओ. (ई)अम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, रोहतक, द्वे विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा भ्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत प्रबन्धवा सम्बन्धित मामला है:—

यद्या श्री कर्मवीर सिंह की सेवाओं का समापन व्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हवदार है ?